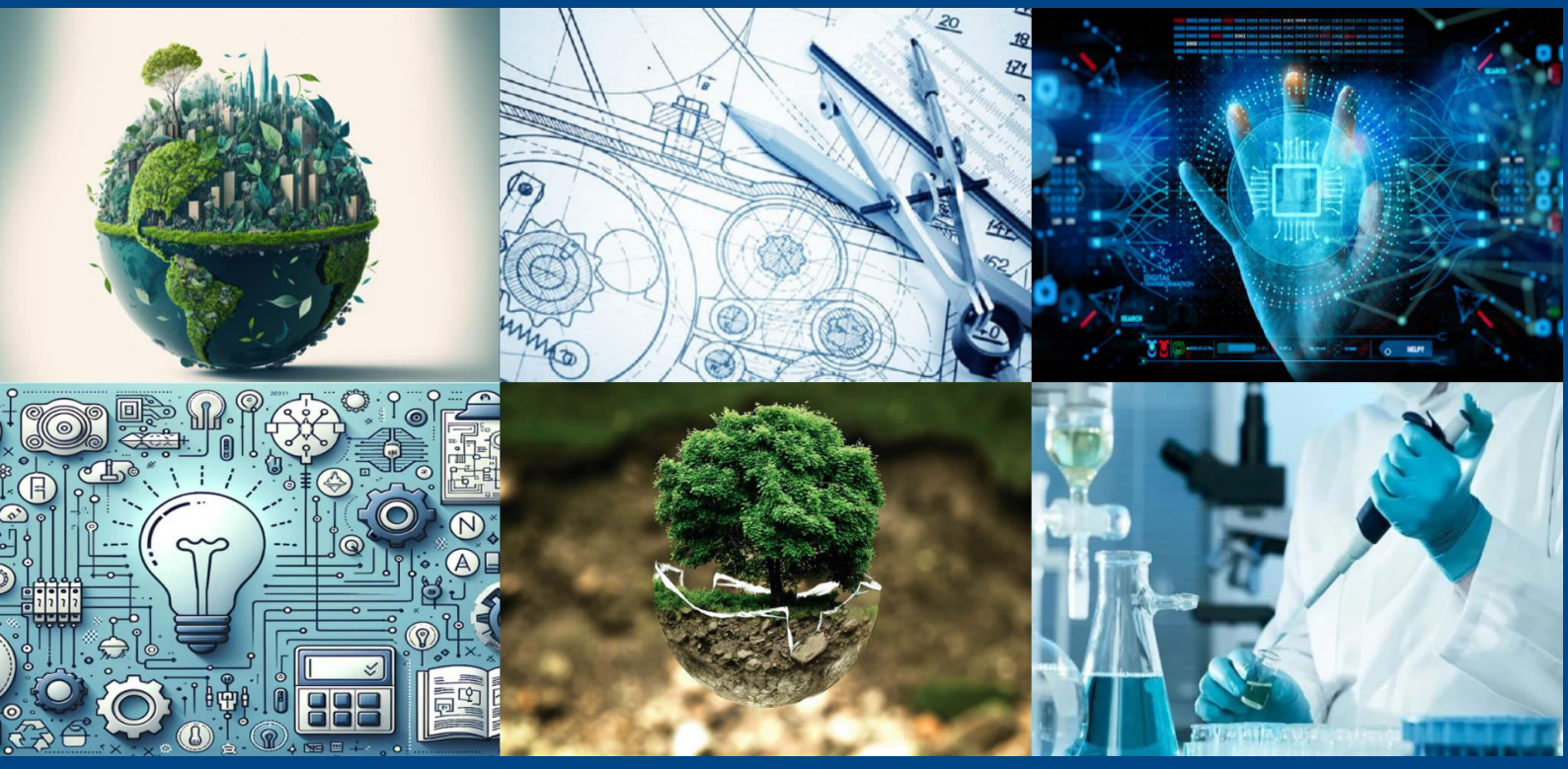
ISSN: 2582-7219



# International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology

*(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)*



**Impact Factor: 9.864**

**Volume 9, Issue 11, November 2026**

© 2026 IJMRSET | Volume 9, Issue 11, November 2026| DOI:10.15680/IJMRSET.2026.0911012

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 9.864| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

# भारत में डिजिटल शासन एवं प्रशासनिक जबावदेही को सुदृढ़ बनाने में सूचना के अधिकार की भूमिका: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

**Akash Kumar, Dr. Ashish Kumar Gupta**

Assistant Professor, Department of Political Science, N.M.S.N. Dass P.G. College, Budaun, Uttar Pradesh, India

Assistant Professor, Department of Political Science, N.M.S.N. Dass P.G. College, Budaun, Uttar Pradesh, India

**सारांश (ABSTRACT):** भारत में डिजिटल शासन का विकास प्रशासनिक पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संदर्भ में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करने वाला एक प्रभावी कानूनी साधन है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल शासन एवं प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने में सूचना के अधिकार की भूमिका का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों, सरकारी रिपोर्टों, संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा पूर्ववर्ती शोध साहित्य पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाता है। अध्ययन में डिजिटल RTI प्रणालियों की उपयोगिता, सूचना तक पहुँच, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का परीक्षण किया गया है। अंततः, अध्ययन डिजिटल समावेशन, समयबद्ध सूचना उपलब्धता और प्रभावी निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है।

**मुख्य शब्द:** सूचना का अधिकार, डिजिटल शासन, प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस, नागरिक भागीदारी।

## I. प्रस्तावना (INTRODUCTION)

डिजिटल शासन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रशासनिक पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता तथा जवाबदेही को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग ने नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँचने और प्रशासनिक निर्णयों की निगरानी करने के नए अवसर प्रदान किए हैं। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, एक ऐसा कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उत्तरदायी शासन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रभावी शासन पद्धतियों का संबंध जनविश्वास, संस्थागत कार्यक्षमता और प्रशासनिक जवाबदेही से होता है [1]।

डिजिटल शासन और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच संबंध केवल ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना सुलभ, विश्वसनीय और नागरिकों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। डिजिटल शासन से संबंधित शोध यह संकेत देता है कि पारदर्शिता और नागरिक संतुष्टि संस्थागत ईमानदारी की जनधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण कारक हैं [2]। इसी प्रकार, सूचना के अधिकार संबंधी कानूनों की प्रभावशीलता पर किए गए अध्ययन प्रशासनिक प्रतिक्रिया और संस्थागत क्रियान्वयन के महत्व को रेखांकित करते हैं [3]। ये पहलू भारत के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, जहाँ डिजिटल तकनीक सूचना तक पहुँच को आसान बना सकती है, लेकिन समयबद्ध और प्रभावी सूचना उपलब्धता की स्वतः गारंटी नहीं देती।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, नागरिकों को निर्धारित कानूनी अपवादों के अधीन सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सूचनाओं के स्वैच्छिक प्रकटीकरण पर भी बल देती है, जिससे व्यक्तिगत आवेदन करने की आवश्यकता कम हो सकती है। डिजिटल RTI पोर्टल आवेदन जमा करने, शुल्क भुगतान करने और आवेदन की स्थिति जानने की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। हालाँकि, इनकी प्रभावशीलता डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट की उपलब्धता, संस्थागत क्षमता और प्रदान की गई सूचना की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सूचना तक प्रभावी पहुँच के लिए मीडिया एवं सूचना साक्षरता भी आवश्यक है, क्योंकि इससे नागरिक उपलब्ध जानकारी को समझने और उसका उपयोग करने में सक्षम होते हैं [4]।

© 2026 IJMRSET | Volume 9, Issue 11, November 2026| DOI:10.15680/IJMRSET.2026.0911012

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 9.864| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

ब्लॉकचेन आधारित पहचान प्रणालियों तथा आधुनिक डिजिटल अवसंरचना जैसी उभरती तकनीकें सरकारी सूचनाओं के सुरक्षित प्रबंधन और पारदर्शिता को बेहतर बनाने की संभावनाएँ प्रस्तुत करती हैं [5], [6]। इसके बावजूद, तकनीक आधारित शासन के लिए उचित संस्थागत सुरक्षा उपाय, समावेशी पहुँच और स्पष्ट जवाबदेही तंत्र आवश्यक हैं। ई-गवर्नेंस के मूल्यांकन से संबंधित शोध भी इस बात पर बल देता है कि डिजिटल पहलों का आकलन केवल तकनीकी क्रियान्वयन के आधार पर नहीं, बल्कि व्यापक शासन मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए [7]। इसके अतिरिक्त, डिजिटल अवसंरचना की परिचालन दक्षता और पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान देना भी सतत डिजिटल शासन के लिए आवश्यक है [8]।

इन विकासों के बावजूद, सूचना उपलब्ध कराने में विलंब, स्वैच्छिक प्रकटीकरण की सीमाएँ, डिजिटल असमानता और जनजागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में डिजिटल शासन एवं प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने में सूचना के अधिकार की भूमिका का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन कानूनों, सरकारी रिपोर्टों और संबंधित अकादमिक साहित्य पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाता है। इसमें पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी, संस्थागत प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अध्ययन का मुख्य तर्क है कि सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म, समयबद्ध सूचना प्रकटीकरण, प्रभावी निगरानी और जवाबदेह सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से डिजिटल शासन तथा सूचना के अधिकार को एक-दूसरे का पूरक बनाया जा सकता है।

## II. साहित्य समीक्षा (REVIEW OF LITERATURE)

डिजिटल शासन, सूचना का अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच संबंध को समझने के लिए पूर्ववर्ती शोध का अध्ययन आवश्यक है। उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि डिजिटल तकनीक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता, नागरिक भागीदारी, सूचना प्रबंधन और प्रशासनिक निगरानी को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। हालाँकि, डिजिटल प्रणालियों की वास्तविक प्रभावशीलता तकनीकी सुविधाओं के साथ-साथ संस्थागत पारदर्शिता, नागरिकों के विश्वास और जवाबदेही तंत्र पर भी निर्भर करती है [9], [14], [16]।

ई-गवर्नेंस में स्व-संप्रभु पहचान (Self-Sovereign Identity) और ब्लॉकचेन आधारित समाधानों का उपयोग सुरक्षित सूचना प्रबंधन, वित्तीय अनुपालन तथा नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बेहतर बनाने की संभावनाएँ प्रस्तुत करता है [9]। ऐसी तकनीकें डिजिटल लेन-देन की विश्वसनीयता और सूचना प्रणालियों की पारदर्शिता को मजबूत करने में सहायक हो सकती हैं। फिर भी, तकनीकी सुरक्षा अपने आप सार्वजनिक सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करती। इसके लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान, प्रभावी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण भी आवश्यक है।

डिजिटल शासन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू हरित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। डिजिटल सरकारी संचालन में ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की रणनीतियाँ प्रशासनिक दक्षता के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दे सकती हैं [10]। हालाँकि, डिजिटल शासन की सफलता का मूल्यांकन केवल तकनीकी दक्षता या पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह भी देखना आवश्यक है कि डिजिटल सेवाएँ विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों के नागरिकों के लिए कितनी सुलभ हैं तथा क्या वे सरकारी सूचनाओं तक समान रूप से पहुँच सकते हैं।

ई-भागीदारी से संबंधित अध्ययन सरकारी निर्णय-प्रक्रिया में नागरिकों की प्रतिक्रिया को शामिल करने के महत्व पर बल देते हैं [11]। नागरिकों की भूमिका केवल सरकारी सूचना प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें नीतिगत प्रक्रियाओं और प्रशासनिक सुधारों में भाग लेने के अवसर भी मिलने चाहिए। सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है, जबकि ई-भागीदारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया, संवाद और सार्वजनिक परामर्श को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार, दोनों व्यवस्थाएँ मिलकर सहभागी और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा दे सकती हैं [17]।

डिजिटल तकनीकों का उपयोग सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, डीप लर्निंग आधारित तकनीकों के साथ रिफ्लेक्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिंग का उपयोग ऐतिहासिक वस्त्रों के विश्लेषण और वर्गीकरण में किया जा सकता है [12]। हालाँकि, इस तकनीकी संदर्भ में प्रयुक्त RTI का अर्थ भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम से भिन्न है। इसलिए डिजिटल शासन और सूचना के अधिकार पर शोध करते समय संबंधित अवधारणाओं के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना आवश्यक है।

© 2026 IJMRSET | Volume 9, Issue 11, November 2026| DOI:10.15680/IJMRSET.2026.0911012

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 9.864| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

ई-गवर्नेंस की भूमिका को राष्ट्रीय छवि, संस्थागत विश्वसनीयता और सार्वजनिक प्रशासन के भविष्य के संदर्भ में भी देखा गया है [13], [14]। डिजिटल सरकारी सेवाएँ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सेवा वितरण में सुधार करने और नागरिकों के साथ संवाद को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती हैं। इसके बावजूद, केवल ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता से प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए सूचना का समयबद्ध प्रकटीकरण, निर्णयों का उचित दस्तावेजीकरण और शिकायतों के प्रभावी निवारण की व्यवस्था भी आवश्यक है।

प्रभावी शासन में साक्ष्य-आधारित निगरानी का विशेष महत्व है। प्रशासनिक प्रदर्शन का मूल्यांकन उपलब्ध आँकड़ों और विश्वसनीय दस्तावेजों के आधार पर किया जाना चाहिए। भारत में सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदनों, अपीलों, निस्तारण और स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण के उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण प्रशासनिक जवाबदेही की स्थिति को समझने में उपयोगी हो सकता है। साक्ष्य-आधारित निगरानी पर उपलब्ध शोध इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है [15]। हालाँकि, किसी अन्य देश में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों को भारतीय परिस्थितियों पर लागू करने से पहले कानूनी, सामाजिक और संस्थागत भिन्नताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

डिजिटल शासन में नागरिकों का विश्वास भी एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहते हैं या नागरिकों की शिकायतों का उचित समाधान नहीं होता, तो संस्थागत विश्वास प्रभावित हो सकता है [16]। इसी प्रकार, लोकतांत्रिक शासन में नागरिक भागीदारी और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है [17]। दक्षिण एशियाई देशों में स्थानीय शासन और नागरिक चार्टर से संबंधित अध्ययन भी प्रशासनिक उत्तरदायित्व, सेवा मानकों तथा नागरिकों के अधिकारों के महत्व को रेखांकित करते हैं [18]।

भारत की ई-गवर्नेंस प्रणालियों में तकनीकी अंतर-संचालनीयता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। विभिन्न सरकारी विभागों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच समन्वय की कमी से सूचना साझा करने, सेवाओं के एकीकरण और नागरिकों की पहुँच में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं [19]। दूसरी ओर, परिवहन नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित शोध वर्तमान विषय के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक नहीं है; इसलिए इसे मुख्य तर्क के आधार के रूप में उपयोग करना उचित नहीं होगा [20]।

## III. शोध के उद्देश्य एवं शोध प्रश्न

### 3.1 शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में डिजिटल शासन एवं प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने में सूचना के अधिकार की भूमिका का विश्लेषण करना है। इसके विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. भारत में डिजिटल शासन और सूचना के अधिकार के बीच संबंध का अध्ययन करना।
2. प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने में RTI की भूमिका का विश्लेषण करना।
3. डिजिटल RTI प्रणाली के माध्यम से नागरिकों की सूचना तक पहुँच का मूल्यांकन करना।
4. सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख तकनीकी, प्रशासनिक एवं सामाजिक चुनौतियों की पहचान करना।
5. डिजिटल शासन के माध्यम से RTI व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

### 3.2 शोध प्रश्न

- डिजिटल शासन भारत में सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन को किस प्रकार प्रभावित करता है?
- प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने में RTI की क्या भूमिका है?
- डिजिटल RTI प्रणाली के सामने प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?
- RTI व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

## IV. शोध पद्धति (RESEARCH METHODOLOGY)

प्रस्तुत अध्ययन में भारत में डिजिटल शासन एवं प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने में सूचना के अधिकार की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है। यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, सरकारी रिपोर्टों, सूचना आयोगों के दस्तावेजों, संबंधित नीतिगत प्रकाशनों तथा उपलब्ध शोध साहित्य का अध्ययन किया जाता है।

© 2026 IJMRSET | Volume 9, Issue 11, November 2026| DOI:10.15680/IJMRSET.2026.0911012

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 9.864| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

अध्ययन के लिए सूचना के अधिकार से संबंधित कानूनी प्रावधानों, डिजिटल आवेदन प्रणालियों, स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण, प्रशासनिक प्रतिक्रिया और नागरिकों की सूचना तक पहुँच जैसे प्रमुख पहलुओं को विश्लेषण की इकाइयों के रूप में निर्धारित किया गया है। इन पहलुओं के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाता है कि डिजिटल तकनीक सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस सीमा तक सरल बनाती है तथा प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने में किस प्रकार योगदान दे सकती है।

अध्ययन में विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) और तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। विषयवस्तु विश्लेषण के माध्यम से संबंधित कानूनों, सरकारी दस्तावेजों और शोध लेखों में प्रस्तुत प्रमुख विचारों एवं निष्कर्षों की पहचान की जाती है। तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत डिजिटल और पारंपरिक RTI प्रक्रियाओं की पहुँच, सुविधा, सूचना उपलब्धता तथा प्रक्रियागत सीमाओं की तुलना की जाती है।

इसके अतिरिक्त, यदि पर्याप्त और तुलनीय सरकारी आँकड़े उपलब्ध हों, तो RTI आवेदनों, अपीलों और निस्तारण से संबंधित रुझानों का विश्लेषण किया जा सकता है। अध्ययन में केवल प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। चूँकि यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, इसलिए इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण या साक्षात्कार के माध्यम से डेटा संग्रह का दावा नहीं किया गया है।

इस अध्ययन की प्रमुख सीमा यह है कि विभिन्न विभागों में डिजिटल RTI प्रणालियों की कार्यप्रणाली और उपलब्ध आँकड़ों की गुणवत्ता अलग-अलग हो सकती है। इसलिए निष्कर्षों की व्याख्या उपलब्ध साक्ष्यों के संदर्भ में की जाएगी।

## V. डिजिटल शासन एवं सूचना के अधिकार का वैधानिक आधार

भारत में डिजिटल शासन और सूचना के अधिकार का वैधानिक आधार नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करने तथा सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना तथा नागरिकों को सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है।

अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। धारा 4 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सूचनाओं के स्वैच्छिक प्रकटीकरण से संबंधित है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि नियमित रूप से सूचना सार्वजनिक किए जाने पर नागरिकों को प्रत्येक जानकारी के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता कम हो सकती है। वहीं, धारा 6 सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है और धारा 7 आवेदन के निस्तारण तथा सूचना उपलब्ध कराने की समय-सीमा से संबंधित है। धारा 8 में कुछ श्रेणियों की सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट देने के प्रावधान हैं।

डिजिटल शासन के विस्तार ने सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए नए अवसर उत्पन्न किए हैं। ऑनलाइन RTI पोर्टल के माध्यम से पात्र सरकारी प्राधिकरणों के लिए आवेदन जमा करने, शुल्क का भुगतान करने और आवेदन की स्थिति देखने जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसी प्रकार, डिजिटल माध्यम सरकारी दस्तावेजों के व्यवस्थित प्रबंधन और सूचनाओं के प्रसार में सहायक हो सकते हैं।

हालाँकि, डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपलब्धता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से सूचना प्राप्त हो रही है। इंटरनेट की सीमित उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता की कमी और तकनीकी समस्याएँ सूचना तक पहुँच को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए डिजिटल शासन को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी अधिकारों, तकनीकी सुविधाओं और समावेशी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच समन्वय आवश्यक है।

इस प्रकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और डिजिटल शासन व्यवस्था एक-दूसरे के पूरक हैं। कानून नागरिकों के सूचना संबंधी अधिकारों का आधार प्रदान करता है, जबकि डिजिटल तकनीक सूचना के प्रसार और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता कर सकती है। दोनों की प्रभावशीलता उचित क्रियान्वयन, समयबद्ध प्रतिक्रिया और संस्थागत जवाबदेही पर निर्भर करती है।

© 2026 IJMRSET | Volume 9, Issue 11, November 2026| DOI:10.15680/IJMRSET.2026.0911012

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 9.864| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

## VI. डिजिटल शासन एवं प्रशासनिक जवाबदेही में RTI की भूमिका

डिजिटल शासन के संदर्भ में सूचना का अधिकार प्रशासनिक पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और सरकारी कार्यों की निगरानी को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से निर्णयों, योजनाओं, व्यय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित सूचना कानून के अंतर्गत प्रकटीकरण योग्य हो।

सबसे पहले, RTI सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। जब नागरिक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट के उपयोग और प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो सार्वजनिक संस्थानों के कार्यों की निगरानी करना आसान हो जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता कर सकते हैं।

दूसरे, RTI प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करता है। सूचना माँगने और निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अपील करने की सुविधा से सार्वजनिक अधिकारियों को कानूनी दायित्वों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। हालाँकि, केवल सूचना प्राप्त होना किसी प्रशासनिक अनियमितता का समाधान नहीं है; प्रभावी कार्रवाई और उचित शिकायत निवारण भी आवश्यक हैं।

तीसरे, डिजिटल शासन नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है। ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति की जानकारी और डिजिटल रूप में उपलब्ध सरकारी दस्तावेज नागरिकों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में सहायता कर सकते हैं। इससे नागरिक सरकारी योजनाओं और सेवाओं के संबंध में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं।

चौथे, RTI भ्रष्टाचार और संसाधनों के अनुचित उपयोग की पहचान में सहायक हो सकता है। सरकारी व्यय, निविदाओं और योजनाओं से संबंधित सूचना प्राप्त करके नागरिक संभावित अनियमितताओं पर प्रश्न उठा सकते हैं। फिर भी, RTI को भ्रष्टाचार समाप्त करने का स्वतः प्रभावी उपाय मानने के बजाय इसे व्यापक निगरानी एवं जवाबदेही व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखना चाहिए।

अंततः, डिजिटल शासन और सूचना का अधिकार तभी प्रभावी रूप से प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ कर सकते हैं, जब सूचना समय पर उपलब्ध हो, डिजिटल सेवाएँ नागरिकों के लिए सुलभ हों और संबंधित संस्थाएँ अपने कानूनी दायित्वों का पालन करें।

## VII. विश्लेषण एवं चर्चा (ANALYSIS AND DISCUSSION)

भारत में डिजिटल शासन एवं प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने में सूचना का अधिकार (RTI) की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए सूचना तक पहुँच, प्रशासनिक पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी तथा सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जैसे प्रमुख पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने, आवेदन की स्थिति देखने और सरकारी सूचनाओं तक पहुँचने में सहायता प्रदान करते हैं। हालाँकि, इन सुविधाओं की वास्तविक प्रभावशीलता प्रशासनिक प्रतिक्रिया, डिजिटल साक्षरता और संस्थागत क्षमता पर निर्भर करती है।

तालिका 1. डिजिटल एवं पारंपरिक RTI प्रक्रिया का तुलनात्मक विश्लेषण

| विश्लेषण का आधार | पारंपरिक RTI प्रक्रिया | डिजिटल RTI प्रक्रिया |
|---|---|---|
| आवेदन जमा करना | डाक या व्यक्तिगत रूप से | ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जहाँ सुविधा उपलब्ध हो |
| आवेदन की स्थिति | डाक या कार्यालय से जानकारी | पोर्टल पर स्थिति देखना, यदि सुविधा उपलब्ध हो |
| भौगोलिक पहुँच | कार्यालय तक पहुँच की आवश्यकता हो सकती है | इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ आवेदन संभव |
| समय एवं लागत | यात्रा, डाक और संबंधित खर्च संभव | यात्रा की आवश्यकता कम हो सकती है |
| डिजिटल साक्षरता | अपेक्षाकृत कम तकनीकी आवश्यकता | इंटरनेट एवं डिजिटल कौशल आवश्यक |
| सूचना की उपलब्धता | संबंधित कार्यालय की प्रक्रिया पर निर्भर | डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन प्रकटीकरण से सुविधा संभव |
| प्रमुख सीमा | भौतिक प्रक्रिया और दस्तावेजों की आवाजाही | तकनीकी बाधाएँ, डिजिटल विभाजन और ऑनलाइन सुविधा की सीमाएँ |

© 2026 IJMRSET | Volume 9, Issue 11, November 2026| DOI:10.15680/IJMRSET.2026.0911012

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 9.864| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

व्याख्या: तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि डिजिटल RTI प्रक्रिया आवेदन और निगरानी को सरल बनाने की क्षमता रखती है। ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों को संबंधित कार्यालय तक व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता कम हो सकती है। इसके विपरीत, इंटरनेट की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव और पोर्टल की तकनीकी समस्याएँ कुछ नागरिकों के लिए बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए डिजिटल प्रणाली को पारंपरिक आवेदन विकल्पों का पूर्ण विकल्प बनाने के बजाय नागरिकों के लिए अतिरिक्त सुविधाजनक माध्यम के रूप में विकसित करना उचित है। यह तुलना प्रक्रियागत विशेषताओं पर आधारित है, न कि किसी सर्वेक्षण से प्राप्त संख्यात्मक निष्कर्षों पर।

तालिका 2. प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने में RTI की भूमिका एवं सुधार के क्षेत्र

| **प्रमुख आयाम** | **RTI की संभावित भूमिका** | **आवश्यक सुधार** |
|---|---|---|
| पारदर्शिता | सरकारी निर्णयों एवं व्यय संबंधी सूचना तक पहुँच | धारा 4 के अंतर्गत स्वैच्छिक प्रकटीकरण मजबूत करना |
| प्रशासनिक जवाबदेही | अधिकारियों के निर्णयों की जाँच में सहायता | समयबद्ध उत्तर एवं प्रभावी निगरानी |
| नागरिक भागीदारी | सरकारी कार्यों पर प्रश्न पूछने का अवसर | जनजागरूकता और नागरिक प्रशिक्षण |
| भ्रष्टाचार पर नियंत्रण | संभावित अनियमितताओं की पहचान में सहायता | शिकायत निवारण एवं उचित कार्रवाई |
| डिजिटल समावेशन | ऑनलाइन माध्यम से सूचना प्राप्त करने की सुविधा | स्थानीय सहायता केंद्र एवं वैकल्पिक आवेदन माध्यम |
| सूचना प्रबंधन | सरकारी रिकॉर्ड तक व्यवस्थित पहुँच | रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और विभागीय समन्वय |

व्याख्या: तालिका 2 दर्शाती है कि सूचना का अधिकार केवल सूचना प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने वाला कानूनी माध्यम भी है। स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और समयबद्ध प्रतिक्रिया से अनावश्यक आवेदनों को कम करने तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता मिल सकती है। हालाँकि, RTI से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई होना भी आवश्यक है। इस प्रकार, डिजिटल तकनीक, कानूनी प्रावधान और जवाबदेह संस्थागत प्रक्रियाओं का समन्वय अधिक प्रभावी शासन व्यवस्था के निर्माण में सहायक हो सकता है।

## VIII. प्रमुख चुनौतियाँ एवं सुझाव

भारत में डिजिटल शासन के विस्तार के बावजूद सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का समाधान प्रशासनिक सुधार, तकनीकी सुविधाओं और नागरिक जागरूकता के समन्वय से किया जा सकता है।

1. डिजिटल विभाजन: ग्रामीण क्षेत्रों और सीमित डिजिटल साक्षरता वाले नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई हो सकती है। इसके लिए सहायता केंद्र, सरल पोर्टल और वैकल्पिक ऑफलाइन आवेदन व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
2. सूचना उपलब्ध कराने में विलंब: आवेदन के निस्तारण में देरी से RTI का व्यावहारिक महत्व कम हो सकता है। संबंधित प्राधिकरणों को निर्धारित कानूनी समय-सीमा का पालन करना चाहिए तथा लंबित मामलों की नियमित निगरानी करनी चाहिए।
3. स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण की कमी: सरकारी सूचनाओं को नियमित रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराने से नागरिकों की निर्भरता व्यक्तिगत आवेदनों पर कम हो सकती है। इसलिए धारा 4 के अंतर्गत प्रकटीकरण को अधिक व्यवस्थित और अद्यतन बनाया जाना चाहिए।
4. तकनीकी एवं प्रशासनिक समन्वय: विभागों के बीच रिकॉर्ड प्रबंधन और सूचना साझा करने की समस्याएँ प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। इसके लिए रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, मानकीकृत प्रक्रियाएँ और अधिकारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है।
5. जनजागरूकता का अभाव: नागरिकों को RTI आवेदन, अपील और कानूनी अधिकारों की पर्याप्त जानकारी नहीं हो सकती। जागरूकता अभियान तथा स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण के माध्यम से इस समस्या को कम किया जा सकता है।

अंततः, डिजिटल शासन में सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए केवल तकनीकी सुविधाओं का विस्तार पर्याप्त नहीं है। समयबद्ध सूचना उपलब्धता, समावेशी पहुँच, बेहतर प्रशासनिक निगरानी और कानूनी दायित्वों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन उपायों से पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करने में सहायता मिल सकती है।

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 9.864| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

## IX. निष्कर्ष (CONCLUSION)

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में डिजिटल शासन एवं प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है तथा प्रशासनिक पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और सरकारी कार्यों की निगरानी को प्रोत्साहित करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने, उसकी स्थिति जानने और सरकारी सूचनाओं तक पहुँचने की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

हालाँकि, डिजिटल शासन की प्रभावशीलता केवल तकनीकी सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती। डिजिटल विभाजन, सीमित डिजिटल साक्षरता, सूचना उपलब्ध कराने में विलंब, स्वैच्छिक प्रकटीकरण की कमी तथा विभागीय समन्वय जैसी चुनौतियाँ RTI के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ पारंपरिक आवेदन माध्यमों की उपलब्धता, समयबद्ध निस्तारण और नागरिक जागरूकता पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूचना का अधिकार और डिजिटल शासन एक-दूसरे के पूरक हैं। धारा 4 के अंतर्गत स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण को मजबूत करना, सरकारी रिकॉर्ड का व्यवस्थित डिजिटलीकरण, अधिकारियों का प्रशिक्षण और प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करना आवश्यक है। अंततः, इन उपायों का समन्वित क्रियान्वयन भारत में पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है।

## संदर्भ सूची (REFERENCES)

1. Abdi, AN.M., Mulyanyuma, A.A. & Niringiyimana, J. A quantitative systematic review of governance practices and public trust in local governments across emerging and developing contexts. *Discov glob soc* **4**, 198 (2026). https://doi.org/10.1007/s44282-026-00558-5
2. Abedi, M., Aplin, T., Gane, E. *et al.* Trajectory and Predictors of Return-to-Work Outcomes for People After a Road Traffic Injury: A Prospective Cohort Study. *J Occup Rehabil* (2026). https://doi.org/10.1007/s10926-026-10380-0
3. Adnan, S., Islam, M.N. Officials' perceptions on the effectiveness of the RTI act 2009 in fulfilling SDG 16.6: a statistical deep dive into the Bangladeshi context. *SN Soc Sci* **5**, 196 (2025). https://doi.org/10.1007/s43545-025-01243-1
4. Alasso, M.M., Omar, A.M., Abdi, A.I. *et al.* Digital governance relates to perceived institutional integrity through government transparency and citizen satisfaction in post conflict Mogadishu Somalia. *Discov glob soc* **4**, 200 (2026). https://doi.org/10.1007/s44282-026-00563-8
5. Almulla, A.A., Mahama, I. Elementary teachers' perspectives on RTI programmes in supporting students with learning disabilities in Saudi Arabia. *Humanit Soc Sci Commun* **13**, 974 (2026). https://doi.org/10.1057/s41599-026-07376-9
6. Baliou, A., Panagiotou, N. (2025). Media and Information Literacy and the Right to Access to Information. In: Katsirikou, A. (eds) Advanced Applications on Qualitative and Quantitative Methods in Information Science. QQML2024 2024. Information Systems Engineering and Management, vol 69. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-02932-4_15
7. Bounnite, M.Y. (2026). Optimising E-Governance in Smart Cities Using a Stochastic Approach. In: Kaddouri, H., Latrache, F., Benkhalifa, A., Abidouche, A., Jbira, N. (eds) Smart Cities for Sustainable and Urban Development. Green Energy and Technology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-99001-4_1
8. Fryonanda, H., Widodo, A.P., Nugraheni, D.M.K. *et al.* Towards value-based digital governance: a systematic literature review and integrative meta-framework for E-government success assessment (2017-2026). *Qual Quant* (2026). https://doi.org/10.1007/s11135-026-03004-5
9. J Nair, A., Manohar, S. & Rao A B, S. Self sovereign identity in e-governance: blockchain solutions for fintech compliance and citizen-centric financial services. *Humanit Soc Sci Commun* **12**, 1562 (2025). https://doi.org/10.1057/s41599-025-05880-y
10. Kadam, S., Raj, C., Anawade, P., sharma, D., Wanjari, U. (2026). Green ICT Leadership in E-Governance: Strategies for Reducing the Carbon Footprint of Digital Government Operations. In: Senjyu, T., So-In, C., Joshi, A. (eds) Smart Trends in Computing and Communications. SmartCom 2025. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1462. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-7511-1_41

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 9.864| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

11. Karkin, N., Göçoğlu, V. (2025). An e-Participation Model Proposal for Incorporation of Citizen Feedback into Government Business. In: Citizen Centricity in Public Policy Making. Contributions to Public Administration and Public Policy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-92301-2_7
12. Khawaja, M.A., Gigilashvili, D., Łojewski, T. *et al.* Beyond relighting: RTI for clustering fragmented heritage textiles using deep learning. *npj Herit. Sci.* **14**, 95 (2026). https://doi.org/10.1038/s40494-026-02326-9
13. Maudarbux, R. (2026). The Role of E-Governance in Strengthening National Image and Soft Power. In: Adoui, A. (eds) Artificial Intelligence, Academic Integrity, and the Internationalization of Higher Education. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-19585-2_5
14. Mseer, I., Samhan, A.A.A. (2025). E-governance and the Future of Public Administration. In: Alaali, M., Musleh Al-Sartawi, A.M.A., Aydiner, A.S. (eds) The Paradigm Shift from a Linear Economy to a Smart Circular Economy. Studies in Systems, Decision and Control, vol 586. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87550-2_96
15. Munir, S., Hamid, M. E-Government & the Concept of Evidence Based Monitoring for Effective Governance: A Case of Punjab, Pakistan. *Public Organiz Rev* **26**, 167–208 (2026). https://doi.org/10.1007/s11115-026-00984-8
16. Myeong, S., Kanzamanova, R. When digital trust collapses: an exploratory comparative framework for citizen involvement in digital governance. *Humanit Soc Sci Commun* **13**, 1226 (2026). https://doi.org/10.1057/s41599-026-07348-z
17. Onufreiciuc, R.A. (2026). Enhancing Democratic Governance in Romania: A Comprehensive Analysis of Citizen Participation Initiatives. In: Bandarzewski, K., Małecka-Łyszczek, M., Mączyński, M., Eliasz, K. (eds) Legal and Axiological Determinants of Innovative Democratic Mechanisms in Local Communities of Central, Eastern and Southern European Countries. European Union and its Neighbours in a Globalized World, vol 34. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-20369-4_9
18. Panday, P.K., Ahsan, A.H.M.K. (2026). Accountability and Citizen Charter: A Comparative Analysis of Local Governance in South Asian Countries. In: Local Government Accountability in South Asia. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-95-6631-0_3
19. Raval, C.N., Mehta, D. (2026). Technological Interoperability Issues in E-Governance Systems of India. In: Kaiser, M.S., Xie, J., Joshi, A. (eds) Intelligent Strategies for ICT. ICTCS 2025. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1892. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-20606-0_32
20. Sarmadi, K., Amiri-Aref, M. & Dong, JX. Multimodal distribution network design problem for returnable transport items with uncertainty. *Ann Oper Res* (2026). https://doi.org/10.1007/s10479-026-07035-x



INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

# INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

## IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com